शुक्रवार

www.shukrawaar.com

वर्ष 4 अंक 37 ■ पृष्ठः 12 ■ 09 अगस्त -15 अगस्त 2019 ■ नयी दिल्ली ■ ₹ 5

श्रीनगर के लाल चौक पर यह कैसा सन्नाटा !

हिसाम सिद्दीकी

न ई दिल्ली.श्रीनगर में अखबार बंद है .इंटरनेट बंद है ,फोन मोबाइल बंद है पर यह सन्नाटा सभी को नहीं दिख रहा है .सवाल यह है कि यह कबतक चलेगा कश्मीर में बीते तीन दिनों से कोई अखबार नहीं छपा है. 5 अगस्त की सुबह को आखिर बार अखबार पढ़ने को मिला था. इंडियन जर्नलिज्म रिव्यू ने लिखा है, आज तीसरा दिन है , कश्मीर में अखबार प्रकाशित नहीं हुए. किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, न तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न ही इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी, और न ही एडिटर्स गिल्ड को अवांछित रूप से इसकी कोई चिंता है.दरअसल आरएसएस का पुराना एजेण्डा पूरा करने के लिए तीन सौ तीन (303) लोक सभा सीटों के गुरूर में चूर नरेन्द्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को स्पेशल दर्जा देने वाली संविधान की दफा तीन सौ सत्तर (370) और उसी के मुताल्लिक दफा 35 ए हटाने के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा छीन कर भले ही जारेहाना (आक्रामक) राष्ट्रवाद के समन्दर में अपने वोट बैंक को खूब गोते लगवा दिए हों लेकिन कश्मीर मसला इतनी आसानी से हल हो जाएगा इसपर किसी भी सही सोच के हिन्दुस्तानी को यकीन नहीं है. यह काम करने के लिए पूरे कश्मीर वादी को बंदूकों और रायफलों के साए में रखा गया है यह पहरेदारी कब तक जारी रखी जा सकेगी और क्या किसी भी प्रदेश को फौज और बंदूक दिखा कर काबू में रखा जा सकता है. यह बात शायद वजीर-ए-आजम नरेन्द्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह समझ नहीं सके हैं या समझ भी रहे हैं तो इस ख्याल से अपने मिशन में आगे बढते जा रहे हैं कि ठीक है और दस-बीस लोगों के मरने की भी नौबत आई तो कौन मरेगा? यह कौन ही अपनी जान देकर मोदी और अमित शाह के वोट बैंक को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे. इस तरह फिलहाल तो सरकार के दोनों हाथों में लड्डू नजर आ रहे हैं आगे की आगे देखी जाएगी. कांस्टीट्एंट असम्बली के जरिए इसमें शामिल की गई दफा 370 को इस तरह हटाना संविधान के खिलाफ है. पेशे से सीनियर वकील कई लोक सभा मेम्बरान खुसूनन कांग्रेस के मनीष तिवारी ने यह बात बहस के दौरान राज्य सभा और लोक सभा में कही तो बिल पेश करने वाले होम मिनिस्टर अमित शाह ने यह कह कर उन सबकी दलीलों को हवा में उड़ा दिया कि आपको नहीं पता है हमने जो कुछ कहा है संविधान के ऐन मुताबिक है. इस बिल पर बहस में शरीक होते हुए फिर बहस का जवाब देते हुए अमित शाह ने पूरी तरह से डिक्टेटराना रवैया अख्तियार रखा. पार्लियामेंट में मेम्बरान और वजीर तक एक दूसरे का नाम लेते वक्त उनके नाम के साथ साहब या जी लगाकर ही मुखातिब करते हैं लेकिन अमित शाह ने राज्य सभा में एक नहीं कई बार यह रिवाज भी खत्म कर दिया. खुद से उम्र और सियासी तजुर्बे में काफी बडे.लीडर आफ अपोजीशन को सिर्फ गुलाम नबी कह कर मुखातिब किया. आपने गैर कानूनी तौर पर जम्मू-कश्मीर का रियासत का दर्जा खत्म करके यूनियन टेरिट्री बना दिया तो पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के हिस्से का मुस्तकबिल क्या होगा. नेशनलिस्ट कांग्रेस की सुप्रिया सुले के इस सवाल पर लोक सभा में अमित शाह को गुस्सा आ गया. उन्होंने कहा कि जब मैं जम्मू-कश्मीर की बात करता हूं तो उसमें कश्मीर का वह हिस्सा भी शामिल रहता है जो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया है.

उजैर हसन रिजवी

हिसाम सिद्दीकी जदीद मरकज अखबार के संपादक हैं

बाकी पेज 2 पर

मोदी कश्मीरी पंडितों को क्यों भूल गए

विजय शंकर सिंह

न ई दिल्ली .गुरुवार 8 अगस्त, रात 8 बजे, प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्र को दिया गया संबोधन उनके हर भाषण की तरह ही उत्तम था. वे एक अच्छे वक्ता हैं. मन की बात हम तक खूबसूरती से पहुंचाते हैं. अपने भाषण में उन्होंने जम्मू कश्मीर और लदाख के विकास, वहां के युवाओं के भविष्य बदलने, उनको नए सपने संजोने और उसे पूरा करने की बात कही. जम्मू कश्मीर पुलिस को केंद्रीय पुलिस के समान सुविधाएं और सेवा लाभ देने की बात की, अन्य सुरक्षा बल तथा सेना को भी उनका मनोबल बढ़े ऐसी बातें की. पुलिस, सुरक्षा बल और सेना के शहीद हुए जवानों को याद किया. जेके, लदाख को पर्यटन के मानचित्र पर अहम स्थान दिलाने की बात की. सोलर ऊर्जा, हर्बल औषधि और जम्मू कश्मीर तथा लदाख की वनस्पतियों के विकास की बात की. ईद के दिन सब सामान्य रहेगा यह भी कहा. यह भी कहा कि जैसे पहले विधानसभा थी, विधायक थे, मंत्रिमंडल था और मुख्यमंत्री थे, वह सब जस का तस रहेगा. शांति और विकास उनकी प्राथमिकता रहेगी. पाकिस्तान की चाल कभी सफल नहीं होगी और जम्मू कश्मीर के लिये यह एक नया समय होगा. इस सुंदर और आशा भरे व्याख्यान में कश्मीरी पंडितों के वापसी के संबंध कोई उल्लेख नहीं है. वे हो सकता हो, इस नए बदलाव से वतन वापसी की बेहतर उम्मीद लगा रखे हों, और अपना जिक्र न होने के कारण, थोड़े निराश भी हों. हो सकता है अगले व्याख्यान मे उनके लिये कुछ ठोस योजनाएं हों . कुछ महत्वपूर्ण केंद्रीय कानून जो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है, जैसे, शिक्षा का अधिकार, न्यूनतम मजदूरी कानून, एससीएसटी एक्ट, आदि अब आसानी से लागू किये जा सकेंगे. भाषण में कुछ तथ्यात्मक भूले भी हैं जो अक्सर पीएम के भाषणों में हो जाती हैं. जैसे अनुच्छेद 370 ने देश को अलगाव वाद और आतंकवाद के रास्ते पर धकेला है. जबकि यह अनुच्छेद 370, सन 1957 से प्रभावी है और कश्मीर 1989 तक शांत था. आतंक का कारण पाकिस्तान तथा तालिबान आदि कट्टरपंथी तत्व हैं. यह भी कहना सही नहीं है कि इस अनु को किसी सरकार ने नहीं बदला, **बाकी पेज 2 पर**

जब पंडितों को निकाला गया तो आप कहां थे ?

अशोक कुमार पांडेय

न ई दिल्ली .आप कश्मीर का क लिखिये तुरन्त कोई प लेकर आ जायेगा. मानो कश्मीर में जितना कुछ हो रहा है, होगा सब पंडितों के नाम पर जस्टिफाई किया जा सकता है. एक ही सवाल - जब पंडितों को घाटी से निकाला गया तो आप कहां थे.अब मैं तो अक्सर पलट के पूछ लेता हूँ कि भाई मैं तो देवरिया में था आप कहां थे. वैसे जब यह हुआ तो सरकार वीपी सिंह की थी, भाजपा का भी समर्थन था उसे और जगमोहन साहब को भेजा उसी के कहने पर गया था. लेकिन थोड़ा इस पर बात कर लेनी जरूरी है.

1989 के हालात क्या थे? सही या गलत लेकिन सच यही है कि पूरी घाटी में आजादी का माहौल बना दिया गया था. जे के एल एफ के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन के पीछे बहुत कुछ था. आंदोलन तो साठ के दशक में अल फतेह ने भी शुरू किया लेकिन उसका कोई खास असर न हुआ था. 1990 के आन्दोलन में उभार बड़ा था. इस पागलपन में जो उन्हें भारत समर्थक लगा, उसे मार दिया गया. दूरदर्शन के निदेशक लासा कौल मारे गए क्योंकि दूरदर्शन को भारत का भोंपू कहा गया तो मुसलमानों के धर्मगुरु मीरवाइज मारे गए क्योंकि वे आतंकवाद को समर्थन नहीं दे रहे थे. मकबूल बट्ट को फांसी की सजा सुनाने वाले नीलकांत गंजू मारे गए तो हजरत साहब के बाल को मिल जाने पर वेरिफाई करने वाले 84 साल के मौलाना मदूदी भी मारे गए. भाजपा के टीका लाल टिपलू मारे गए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद यूसुफ हलवाई भी मारे गए. कश्मीरी पंडित आईबी के लोग मारे गए तो इंस्पेक्टर अली मोहम्मद वटाली भी मारे गए. सूचना विभाग में डायरेक्टर पुष्कर नाथ हांडू मारे गए तो कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रो मुशीरुल हक भी मारे गए. पंडितों के माइग्रेशन का विरोध कर रहे हदयनाथ वांचू मारे गए तो पूर्व विधायक मीर मुस्तफा और बाद में अब्दुल गनी लोन भी मारे गए. जिन महिला नर्स सरला देवी की हत्या और बलात्कार की बात होती है उन पर भी मुखबिर होने का आरोप लगाया गया था. तो वह पागलपन का दौर था. लेकिन क्या सारे मुसलमान खिलाफ थे पंडितों के सारे हत्यारे थे? सोचिये 96 प्रतिशत मुसलमान अगर चार प्रतिशत पंडितों के वाकई खिलाफ हो जाते तो बचता कोई जाहिर है इस पागलपन में बहुत से लोग निरुद्देश्य भी मारे गए. बिट्टा कराटे जैसे लोगों ने साम्प्रदायिक नफरत में डूब कर निदोर्षों को भी मारा. पलायन क्यों हुआ? जाहिर है इन घटनाओं और उस माहौल में पैदा हुए डर और असुरक्षा से. जगमोहन अगर इसके लिए जिम्मेदार नहीं थे तो भी यह तो निर्विवाद है कि इसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की. बावजूद इसके लगा किसी को नहीं था कि वे वापस नहीं लौटेंगे. सबको लगा कुछ दिन में माहौल शांत होगा तो लौट आएंगे. अगर बदला जैसा कुछ होता है तो कश्मीरी

लेखक की पुस्तक कश्मीर और कश्मीरी पंडित जल्द आ रही है .

बाकी पेज 2 पर